मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

सीएसएसआई, जामिया ने 'डिसेबिलिटी एंड सोशल इन्क्लूजन इन इंडिया' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की; एक्सपर्ट्स ने सोच, करिकुलम और नज़रिए को बदलने की अपील की

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इन्क्लूजन (सीएसएसआई) जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएम्आई) ने डीन, एकेडमिक अफेयर्स के कार्यालय के साथ मिलकर 'डिसेबिलिटी एंड सोशल इन्क्लूजन इन इंडिया' पर एक दिवसीय संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया। यह जेएम्आई के माननीय वाइस चांसलर, प्रो. मज़हर आसिफ़ की चीफ पेट्रनशिप और जेएम्आई के रजिस्ट्रार, प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिज़वी की देखरेख में हुआ। जेएम्आई के FTK-CIT हॉल में हुए इस कार्यक्रम में एकेडमिक्स, पॉलिसीमेकर्स, प्रैक्टिशनर्स और छात्रों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया।

'भारत में दिव्यांगता और सामाजिक समावेश: बदलाव का रोडमैप' नाम का सेमिनार पवित्र कुरान की तिलावत और जामिया तराना के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद खास मेहमानों का स्वागत किया गया। अपने स्वागत वक्तव्य में, सीएसएसआई की कार्यवाहक निदेशक और एकेडमिक अफेयर्स की डीन प्रो. तनुजा ने SDG गोल 10 के हिसाब से इन्क्लूजन को फंडामेंटल जस्टिस और प्लूरलिज़्म का मामला बताया, जबकि सेमिनार के समन्वयक डॉ. अरविंद कुमार ने सेंटर के एल्युम्नस मिस्टर फैसल की अचीवमेंट्स की सराहना करते हुए सेंटर की सक्सेस पर ज़ोर दिया, जो अब हेलेन केलर अवॉर्डी हैं।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जॉइंट सेक्रेटरी और विशिष्ट अतिथि डॉ. आशिमा मंगला ने दिव्यांगों को समान, क्रिएटिव नागरिक मानते हुए सोच में बदलाव की वकालत की, जिस पर जेएम्आई की स्टूडेंट वेलफेयर की डीन प्रो. नीलोफर अफजल ने यूनिवर्सिटी लाइफ के फिजिकल, एकेडमिक और सोशल क्षेत्रों में गहरी संवेदनशीलता की बात कहकर चर्चा में और इज़ाफ़ा किया।

इस मौके पर मुख्य अतिथि, जामिया हमदर्द के स्कूल ऑफ़ एलाइड हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च के डीन, प्रो. सोहराब अहमद खान ने बुज़ुर्गों और काम करने वाले लोगों में दिव्यांगता संबंधी सपोर्ट करने के लिए यूजीसी एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की, जबकि एडवोकेट डॉ. के. सी. जॉर्ज, सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव, दीपालय और पूर्व जॉइंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने "इन्क्लुड एवरीवन, एक्सक्लुड नन" की राय दी, और साइन लैंग्वेज लिटरेसी और फैसले लेने की पावर पर ज़ोर दिया।

अपने मुख्य वक्तव्य में, जेएनयु की प्रो. निलिका मेहरोत्रा ने दिव्यांगता के जेंडर और जाति के साथ इंटरसेक्शन पर बात की, और करिकुलम और नज़रिए में बदलाव की मांग की, इसी बात को जेएम्आई के विधि संकाय के असिस्टेंट प्रो. डॉ. रशीद ने भी दोहराया, जिन्होंने ट्रेडिशनल रिसर्च बायस को दूर करने के लिए एक सेंसरी तरीके के तौर पर 'ब्लाइंड एथनोग्राफी' पर चर्चा की।

सेमिनार के संरक्षक, प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिज़वी, रजिस्ट्रार, जेएमआई ने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति की पुष्टि करते हुए और दिव्यांगों को हीन समझने वाले भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को पूरी तरह अस्वीकार करने का आह्वान करते हुए समापन किया। सह-संयोजक डॉ. सबा हुसैन, सीएसएसआई, जेएमआई के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सत्र का समापन हुआ।

पहला तकनीकी सत्र, "भारतीय संदर्भ में विकलांगता पर विमर्श", जिसकी अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रो. राकेश कुमार शर्मा ने की, में समुदाय के सामने आने वाली संरचनात्मक और कानूनी बाधाओं की जांच की गई। प्रो. महेश एस. पणिक्कर, जो एलएसआर, डीयू में पढ़ाते हैं, उन्होंने विकलांगता पर एक राजनीतिक पहचान के रूप में चर्चा की जो विशिष्ट दुर्बलताओं से परे है लेकिन इसके लिए अंतरविषयी, दुर्बलता-विशिष्ट समाधानों की आवश्यकता है और प्रो. जगदीश चंदर, हिंदू कॉलेज, डीयू ने 'सोशल मॉडल' पर ज़ोर दिया, और कहा कि लोग पाबंदियों वाले माहौल से डिसेबल हो जाते हैं।

दूसरे तकनीकी सत्र, "नैरेटिव्स ऑफ़ डिसेबिलिटी: एजेंसी, रिप्रेजेंटेशन, एंड फ्रेमवर्क्स," की अध्यक्षता प्रो. सारिका शर्मा, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ़ एजुकेशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने की। जाने-माने स्पीकर्स ने राइट्स-बेस्ड, इनक्लूसिव, और एजेंसी-सेंटर्ड नज़रिए से डिसेबिलिटी पर बातचीत को फिर से सोचने पर ज़रूरी बातें शेयर कीं। डॉ. तालीम अख्तर, हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली ने डिसेबिलिटी वाले लोगों को एक्टिव डेमोक्रेटिक एजेंट के तौर पर सेंटर में रखने के लिए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को फिर से जांचने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। डॉ. रुबुल कलिता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हरियाणा ने ऐसे इनक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की वकालत की जो चैरिटी-बेस्ड मॉडल से राइट्स-बेस्ड एम्पावरमेंट की ओर शिफ्ट हों। डॉ. मो. तनवीर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने डिसेबिलिटी पर एजुकेशनल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अपने अनुभवों को साझा करने पर ज़ोर दिया। जेएम्आई के ओल्ड स्टूडेंट, मिस्टर फैसल अशरफ नोमानी ने डिसेबिलिटी की कहानियों को बदलने के लिए सेल्फ-एडवोकेसी और विज़िबिलिटी को ज़रूरी बताया। जेएम्आई से जुड़ी सुश्री अन्वेषा बरुआ ने डिसेबिलिटी के अधिकारों को आगे बढ़ाने में पॉलिसी एडवोकेसी और लीडरशिप प्लेटफॉर्म की भूमिका पर ज़ोर दिया।

सीएसएसआई की सह-समन्वयक डॉ. ज्योतिरूपा ने एक इंटरैक्टिव डिस्कशन और धन्यवाद ज्ञापन के साथ सेमिनार खत्म किया। यह सेमिनार भारत में डिसेबिलिटी और सोशल इनक्लूजन पर एकेडमिक एंगेजमेंट और पॉलिसी डिस्कोर्स को मज़बूत करने में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ।

प्रो. साइमा सईद
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी